राष्ट्रीय संस्करण
शनिवार 27 अप्रैल 2019
दैनिक जागरण
बिजनेस
www.jagran.com

पतंजलि की संशोधित बोली पर 30 को होगा फैसला

नई दिल्ली, प्रेट्र : कर्ज में डूबी और इन्सॉल्वेंसी प्रक्रिया का सामना कर रही रुचि सोया के लिए पतंजलि आयुर्वेद की संशोधित बोली पर 30 अप्रैल को फैसला होगा। योगगुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद की ने रुचि सोया के लिए 4,350 करोड़ रुपये की संशोधित बोली दाखिल की है। सूत्रों के मुताबिक रुचि सोया के कर्जदाता अब 30 अप्रैल को मतदान के जरिये फैसला करेंगे। अडानी विल्मर के हट जाने के बाद इस कंपनी के लिए पतंजलि अकेली दावेदार बची है।

आइबीसी में मामला जाने से बच सकने लायक कंपनियां बच भी गई हैं, और कर्जदाताओं को भी संपत्ति बिक्री के मुकाबले ज्यादा रकम मिली है।
— एमएस साहू
चेयरमैन, आइबीबीआइ

सेंसेक्स	39,067.33 ▲ 336.47	निफ्टी	11,754.65 ▲ 112.85	सोना प्रति दस ग्राम	₹ 33,020 ▲ ₹150	चांदी प्रति किलोग्राम	₹ 38,750 ▲ ₹230	$ डॉलर	₹ 70.02 ▼ ₹0.23	क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल	$ 73.09

हालात ▶ ज्यादातर कर्मचारियों का चार महीनों का वेतन है बकाया

जेट स्टाफ को सैलरी मिलने का भरोसा नहीं : सीईओ

सीईओ ने कर्मचारियों को लिखे पत्र में कहा– किसी भी पक्ष से वेतन मिलने का नहीं मिला कोई भरोसा

मुंबई, प्रेट्र : जेट एयरवेज के सीईओ विनय दूबे ने कहा कि काफी दुख की बात है कि कर्मचारियों की सैलरी देने को लेकर किसी भी पक्ष से कोई भरोसा नहीं मिला है। अप्रैल की सैलरी मिलने में कुछ ही दिन रह गए हैं। कंपनी ने 20,000 से अधिक कर्मचारियों को मार्च का वेतन भी नहीं दिया है। बैंकों के समूह से परिचालन और कर्मचारियों के मार्च के वेतन के लिए 983 करोड़ रुपये का आवश्यक फंड नहीं मिलने पर कंपनी ने 17 अप्रैल को विमानों का परिचालन बंद कर दिया था।

दूबे ने शुक्रवार को कर्मचारियों के नाम जारी पत्र में कहा कि कंपनी के लिए खरीदार ढूंढने की बैंक की कोशिश का हम समर्थन करते हैं, लेकिन यह बताते हुए काफी दुख हो रहा है कि अब तक किसी भी पक्ष ने वेतन को लेकर न तो स्थिति स्पष्ट की है और न ही कोई भरोसा दिया है। कंपनी के कर्मचारियों ने शुक्रवार को बांद्रा कुड़ला कांप्लेक्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव रैली स्थल की ओर शांति जुलूस निकालने का फैसला किया था, लेकिन पुलिस और राज्य सरकार के अनुरोध पर उन्होंने इसे रद कर दिया। दूबे ने पत्र में कहा कि एक ओर हमें कहा जा रहा है कि हम बोली प्रक्रिया में जेट एयरवेज के मूल्य को बनाए रखें, दूसरी ओर वेतन नहीं मिलने के कारण हमारे कुछ सहयोगी दूसरी कंपनियों में नौकरी खोजने के लिए मजबूर हैं। इस स्थिति के बारे में बताने पर हमें कहा जा रहा है कि इस समस्या का निदान उन शेयरधारकों को करना है, जिन्हें काफी समय पहले हमारी समाधान योजना पर सहमत हो जाना चाहिए था।

उन्होंने कहा कि बैंकों ने स्पष्ट कह दिया है कि जब तक बोली की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक वे वेतन को लेकर कोई वादा नहीं कर सकते। दूबे ने कहा कि हमने सरकार के उच्च स्तर पर भी संपर्क किया है, लेकिन उसका भी कोई अनुकूल परिणाम नहीं मिला है।

फीचर फोन बाजार पर जियो का कब्जा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : रिलायंस जियोफोन 30 फीसद हिस्सेदारी के साथ इस वर्ष की पहली तिमाही (जनवरी-मार्च, 2019) में भारत के फीचर फोन बाजार का अग्रणी ब्रांड बन गया है। सैमसंग फीचर फोन 15 फीसद की हिस्सेदारी के साथ दूसरे नंबर पर रहा है।

काउंटरपॉइंट रिसर्च की एक रिपोर्ट 'इंडिया स्मार्टफोन मार्केट शेयर क्वार्टर वन-2019' में कहा गया है कि स्मार्टफोन बाजार व्यापक अवसर प्रदान करता है, लेकिन भारतीय बाजार में 40 करोड़ फीचर फोन उपयोगकर्ताओं की अनदेखी नहीं किया जा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू हैंडसेट निर्माता लावा ने 13 फीसद बाजार हिस्सेदारी के साथ तीसरा स्थान हासिल किया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि फीचर फोन का बाजार लगातार बढ़ रहा है। इससे पहले मार्च में रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि 2019 में दुनियाभर में 40 करोड़ से अधिक फीचर फोन की बिक्री होगी। वर्ष 2021 तक फीचर फोन शिपमेंट 100 करोड़ यूनिट को पार करने की उम्मीद है।

ब्रोकरेज फर्म सीएलएसए ने इस वर्ष फरवरी के टेलीकॉम आउटलुक में कहा था कि जियो इस वर्ष सबस्क्राइबर बाजार हिस्सेदारी का नेतृत्व करेगा। फर्म के मुताबिक फरवरी में मोबाइल ग्राहकों की संख्या 20 लाख बढ़कर 118.40 करोड़ हो गई, जिसमें रिलायंस जियो में 80 लाख नए ग्राहक जुड़े। जियो के पास इस समय देश में 30.6 करोड़ का ग्राहक आधार है।

आइजीएसटी क्रेडिट मद से अन्य टैक्स चुका सकते हैं कारोबारी

- मार्च में ही दे दी गई थी अनुमति पर कारोबारियों में अनुपात को लेकर भ्रम था
- कारोबारी आजीएसटी क्रेडिट का जितना चाहें, उतना कर सकते हैं उपयोग

नई दिल्ली, प्रेट्र : इंटिग्रेटेड जीएसटी (आइजीएसटी) क्रेडिट हासिल करने वाली कंपनियां इसका उपयोग केंद्र और राज्य सरकारों के बकाया जीएसटी का किसी भी अनुपात में भुगतान करने में कर सकती हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) ने यूं तो मार्च में ही आइजीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) से सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी का भुगतान किए जाने की मंजूरी दे दी थी। इसके साथ शर्त यह लगाई गई थी कि संपूर्ण आइजीएसटी देनदारी की पहले अदायगी करनी होगी। करदाताओं में हालांकि इस बात को लेकर भ्रम था कि सीजीएसटी और एसजीएसटी के बकाए टैक्स का भुगतान करने में आइजीएसटी क्रेडिट के कितने हिस्से का उपयोग किया जा सकता है।

सीबीआइसी ने ताजा अधिसूचना में इसे स्पष्ट कर दिया है। इसके मुताबिक सीजीएसटी और एसजीएसटी के भुगतान में करदाता जितना चाहें आइजीएसटी क्रेडिट के उतने हिस्से का उपयोग कर सकते हैं। जीएसटी से जुड़े नियमों के मुताबिक आयातकों को आयात किए जाने वाले माल पर आइजीएसटी का भुगतान करना पड़ता है। इसके साथ ही दो राज्यों के बीच माल के परिवहन पर भी आइजीएसटी चुकाना होता है। इस टैक्स को वास्तविक जीएसटी के साथ एडजस्ट किया जा सकता है या कुछ मामलों में इसके रिफंड के लिए क्लेम किया जा सकता है।

जीएसटी प्रणाली के तहत वस्तु की खपत या सेवा की आपूर्ति पर लगने वाले जीएसटी को केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) के बीच आधा-आधा विभाजित किया जाता है। दो राज्यों के बीच माल परिवहन और आयात पर आइजीएसटी लगता है, जो केंद्र के खाते में जाता है। नियमों के मुताबिक वित्त वर्ष की समाप्ति पर आइजीएसटी खाते में बैलेंस शून्य हो जाना चाहिए, क्योंकि इसका उपयोग सीजीएसटी और एसजीएसटी के भुगतान में किया जा सकता है। लेकिन कुछ कारोबारियों को आइटीसी का लाभ क्लेम करने की अनुमति नहीं होती है, जिसके कारण उनके आइजीएसटी मद में बैलेंस खत्म नहीं हो पाता था।

पीएफ पर मिलेगा पिछले वर्ष से ज्यादा ब्याज

- सरकार ने बीते वित्त वर्ष के लिए पीएफ पर 8.65 फीसद ब्याज को दी मंजूरी
- वित्त वर्ष 2017-18 में पीएफ पर दिया था 8.55 फीसद ब्याज

नई दिल्ली, प्रेट्र : वेतनभोगी वर्ग को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने इस वर्ष मार्च में खत्म हुए वित्त वर्ष के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पर 8.65 फीसद ब्याज को मंजूरी दे दी है। यह उससे पिछले वित्त वर्ष के लिए मिली ब्याज दर के मुकाबले 10 आधार अंक (0.10 फीसद) ज्यादा है। इस फैसले से संगठित क्षेत्र के छह करोड़ से ज्यादा वेतनभोगियों को फायदा पहुंचेगा। तीन वर्ष बाद पीएफ अकाउंट पर ब्याज दर में बढ़ोतरी की गई है।

इस बारे में एक सूत्र ने कहा कि वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने पीएफ पर 8.65 फीसद ब्याज को अनुमोदन दे दिया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के बोर्ड ने बीते वित्त वर्ष के लिए पीएफ पर ब्याज के निर्धारण के लिए इस वर्ष फरवरी में बैठक की थी। श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार की अध्यक्षता वाले बोर्ड ने बीते वित्त वर्ष के लिए 8.65 फीसद ब्याज दर की अनुशंसा की थी।

ईपीएफओ के अनुमान के मुताबिक 8.65 फीसद के हिसाब से ब्याज देने के बाद उसके पास 151.67 करोड़ रुपये बच जाएंगे। अगर ब्याज दर बढ़ाकर 8.70 फीसद किया जाता, तो ईपीएफओ को 158 करोड़ रुपये का नुकसान झेलना पड़ता। गौरतलब है कि इससे पिछले वित्त वर्ष (2017-18) के लिए ईपीएफओ ने पीएफ पर 8.55 फीसद ब्याज दिया था। हालांकि वित्त वर्ष 2015-16 में पीएफ पर 8.80 फीसद ब्याज दिया गया था, लेकिन सरकार ने उससे अगले वित्त वर्ष यानी 2016-17 में इसे घटाकर 8.65 फीसद कर दिया।

यस बैंक को 1,506 करोड़ रुपये का घाटा

मुंबई, प्रेट्र : निजी क्षेत्र के कर्जदाता यस बैंक को पिछले वित्त वर्ष की चौथी और आखिरी तिमाही (जनवरी-मार्च, 2019) में 1,506 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा उठाना पड़ा है। उससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में बैंक को 1,179 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था। बैंक ने कहा कि फंसे कर्ज (एनपीए) प्रावधान में नौ गुना बढ़ोतरी के चलते बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में उसे घाटा उठाना पड़ा। इस वर्ष जनवरी में संस्थापक और पूर्व एमडी राणा कपूर के जाने के बाद बैंक के नए प्रबंधन ने पहली बार किसी तिमाही के वित्तीय नतीजे जाहिर किए हैं। बैंक ने कहा कि बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में उसने 3,661 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। इस वजह से इस वर्ष मार्च में खत्म वित्त वर्ष के लिए भी उसका शुद्ध लाभ घटकर 1,720 करोड़ रुपये रह गया। उससे पिछले वित्त वर्ष में बैंक को 4,224 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था। बीएसई को दी एक अलग जानकारी में बैंक ने कहा कि उसके बोर्ड ने चालू वित्त वर्ष के दौरान 20,000 करोड़ रुपये जुटाने को मंजूरी दे दी है।

एनएचएआइ की बढ़ीं मुश्किलें

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

जमीन के बढ़ते मुआवजे के साथ तेल सेस की हिस्सेदारी में कमी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। इससे एनएचएएआइ को कर्जों पर ब्याज अदा करने में दिक्कत हो रही है। साथ ही सड़क परियोजनाओं की रफ्तार भी प्रभावित हो रही है।

सड़क परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एनएचएआइ हर साल बाजार से हजारों करोड़ रुपये का कर्ज जुटाता है। सड़क निर्माण की रफ्तार के साथ जमीन पर मुआवजे की रकम बढ़ने से हाल के वर्षों में इस कर्ज में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। पांच वर्ष पहले तक एनएचएआइ हर साल 3-4 हजार करोड़ रुपये जुटाता था। अब यह रकम 17-18 गुना तक बढ़ गई है। वित्त वर्ष 2014-15 में एनएचएआइ ने बाजार से करीब 3,340 करोड़ रुपये ही जुटाए थे। वहीं, 2017-18 में उसने करीब 50 हजार करोड़ रुपये तथा 2018-19 में 62 हजार करोड़ रुपये का कर्ज जुटाया। इस भारी-भरकम कर्ज पर एनएचएआइ को हर साल कई सौ करोड़ की राशि ब्याज के तौर पर चुकानी पड़ रही है।

सरकार से मिलने वाली बजटीय मदद के अलावा एनएचएआइ के पास आय के दो ही स्रोत हैं। एक, रोड सेस से मिलने वाली हिस्सेदारी और दूसरा राजमार्गों पर एकत्र किया जाने वाला टोल टैक्स। हालांकि पिछले पांच वर्षों में दोनो में खासी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन कर्ज में बढ़ोतरी के मुकाबले ये कम है। उदाहरण के लिए 2014-15 में एनएचएआइ को रोड सेस से हिस्सेदारी के तौर पर 9,566 करोड़ रुपये की रकम प्राप्त हुई थी। जबकि वर्ष 2017-18 में यह बढ़कर 25,356 करोड़ रुपये हो गई थी। पिछले साल सरकार ने एक संशोधन के जरिये रोड सेस से एनएचएआइ को प्राप्त होने वाली रकम में से दो फीसद हिस्सा भारतीय जलमार्ग प्राधिकरण को देने का निर्णय लिया था।

स्टर्लिंग मामले में बैंकों को सजा दे सरकार

मुंबई, प्रेट्र : नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने स्टर्लिंग सेज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर को इन्सॉल्वेंसी प्रक्रिया से बाहर निकाले जाने के लिए दी गई अनुमति को शुक्रवार को वापस ले लिया। इसके साथ ही ट्रिब्यूनल ने सरकार को निर्देश दिया कि विदड्रावल याचिका के जरिये उसे गुमराह करने के जुर्म में बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों को सजा दी जाए। एनसीएलटी के इस आदेश के बाद अब स्टर्लिंग सेज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर की संपत्तियों की बिक्री शुरू होगी। कंपनी पर आंध्रा बैंक की अगुवाई वाले बैंकों के समूह का 8,100 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज बकाया है।

गुरुवार को हुई सुनवाई में एनसीएलटी की पीठ ने नाराजगी जताते हुए बैंकों को शुक्रवार की सुनवाई में व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित रहने का आदेश दिया था। इस मामले में भगोड़े प्रमोटर्स द्वारा वन-टाइम सेट्लमेंट का ऑफर दिए जाने के बाद इस महीने के शुरू में कर्जदाताओं की समिति ने कंपनी को बैंक्रप्सी प्रक्रिया से बाहर निकालने के लिए आवेदन दाखिल किया था।

तेजी से बदलेगी डीजल कार बाजार की इकोनॉमी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- डीजल की मांग में इस वर्ष महज तीन फीसद इजाफा की उम्मीद
- बिजली की आपूर्ति बढ़ने और डीजल वाहनों में मांग घटने से बदली स्थिति

देश में अगले वर्ष अप्रैल से बीएस-6 मानक लागू होने के साथ ही डीजल इकोनॉमी में बड़े बदलाव की शुरुआत हो जाएगी। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी पहले ही डीजल कारों की बिक्री बंद करने का एलान कर चुकी है। कुछ दूसरी कार कंपनियां भी अपने कई डीजल संस्करणों को वापस लेने का मन बना लिया है, जिनके बारे में जल्द घोषणा होने की संभावना है। कम से कम एक दर्जन कॉम्पैक्ट कारों के बंद होने की बात कही जा रही है। देश में डीजल की मांग में भी कमी आने के आसार है जिसे देखते हुए तेल कंपनियां भी अपनी रणनीति बदल रही हैं। इन कंपनियों का कहना है कि भविष्य में वे डीजल के बजाय सीएनजी की मार्केटिंग व उत्पादन पर ज्यादा ध्यान देंगी।

पेट्रोलियम मंत्रालय भी यह मानता है कि डीजल मांग की वृद्धि दर अब बहुत सुस्त होगी। मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष के दौरान डीजल की मांग 8.64 करोड़ टन रहने का अनुमान लगाया है जो पिछले वित्त वर्ष से महज तीन फीसद ज्यादा है। कुछ वर्ष पहले तक डीजल की मांग में सालाना छह-सात फीसद का इजाफा होता था। अब मंत्रालय के पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल (पीपीएसी) से जुड़े एक अधिकारी के मुताबिक डीजल की मांग में आने वाले दिनों में बड़ी कमी आ सकती है। इसकी वजह यह है कि सरकार ने लंबी दूरी के चलने वाले ट्रकों में भी सीएनजी के इस्तेमाल की योजना बनाई है। इसके लिए सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के पास सीएनजी स्टेशन खोलने की तैयारी है, ताकि ट्रकों को भी स्वच्छ ईंधन मिल सके। इसके अलावा विद्युतीकरण की वजह से रेलवे में डीजल की खपत कम हो चुकी है। साथ ही बिजली बनाने में डीजल का काफी इस्तेमाल हो रहा था लेकिन बिजली की पर्याप्त आपूर्ति से यहां भी खपत कम हो चुकी है। यही वजह है कि सरकारी तेल कंपनियों की भावी रणनीति अब डीजल से ज्यादा सीएनजी की मार्केटिंग को बढ़ावा देने की है।

डीजल कारों का तेजी से घट रहा है बाजार

पैसेंजर कारों में डीजल कारों की खपत लगातार कम हो रही है। पांच वर्ष पहले देश में बिकने वाली पैसेंजर कारों में डीजल से चलने वाली कारों की हिस्सेदारी 30 फीसद थी जो दिसंबर, 2018 को समाप्त नौ महीनों में घट कर 20 फीसद रह गई है। मारुति सुजुकी जब अगले वर्ष अप्रैल से डीजल चालित पैसेंजर कारों की बिक्री बंद कर देगी तब डीजल की खपत और घट जाएगी। दूसरी कार कंपनियां भी डीजल से चलने वाली छोटी कारों को लेकर गंभीरता से विचार कर रही हैं। बीएस-6 मानक वाले डीजल इंजन को बनाने की लागत काफी ज्यादा होगी। 1,200 सीसी क्षमता के बीएस-4 वाले डीजल इंजन को बीएस-6 में तब्दील करने में 1.50 लाख रुपये तक की लागत आएगी। जबकि पेट्रोल इंजन को बीएस-6 संस्करण में बदलने में सिर्फ 30-40 हजार रुपये की लागत आएगी।

सोना दूसरे दिन भी मजबूत चांदी भी 230 रुपये उछली

- ज्वेलरों के बीच मांग बढ़ने और विदेश के मजबूत रुझानों से सोना चमका
- रुपये के डॉलर के मुकाबले 70 के स्तर पर आने से सोना बना सुरक्षित निवेश

नई दिल्ली, प्रेट्र : विदेश के मजबूत रुझानों के बीच स्थानीय ज्वेलरों के बीच मांग बढ़ने से राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को सोने का भाव 150 रुपये चढ़कर 33,020 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक औद्योगिक इकाइयों और सिक्का निर्माताओं की ओर से खरीदारी बढ़ाए जाने से चांदी भी 230 रुपये की मजबूती के साथ 38,750 रुपये प्रति किलोग्राम की हो गई।

सराफा कारोबारियों ने कहा कि विदेश के मजबूत रुझानों और स्थानीय ज्वेलरों की ओर से खरीदारी बढ़ाए जाने के कारण बहुमूल्य धातु में मजबूती आई। रुपये के डॉलर के मुकाबले 70 के स्तर के आसपास रहने के कारण भी सुरक्षित निवेश के रूप में सोने का आकर्षण बढ़ गया है। न्यूयॉर्क में सोने में 1,282.70 डॉलर प्रति औंस (28.35 ग्राम) पर और चांदी में 15.10 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार हुआ। गुरुवार को भी सोना 150 रुपये प्रति 10 ग्राम उछला था और चांदी भी 295 रुपये प्रति किलोग्राम मजबूत हुई थी।

राष्ट्रीय राजधानी में 99.9 फीसद खरा सोना 150 रुपये चढ़कर 33,020 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया और 99.5 फीसद खरा सोना भी इतनी ही मजबूती के साथ 32,850 रुपये प्रति 10 ग्राम का हो गया। आठ ग्राम सोने की गिन्नी हालांकि 26,400 रुपये प्रत्येक के भाव पर कायम रही।

चांदी हाजिर 230 रुपये की मजबूती के साथ 38,750 रुपये प्रति किलोग्राम की हो गई और वीकली डिलीवरी 179 रुपये चढ़कर 37,560 रुपये प्रति किलोग्राम की हो गई। चांदी के सिक्कों की कीमत प्रति सैकड़ा 80,000 रुपये खरीद और 81,000 रुपये बिक्री के पिछले स्तर पर कायम रही।

चाल

बीएसई सेंसेक्स के ज्यादातर बैंकिंग शेयरों में साप्ताहिक कारोबार के आखिरी दिन उछाल दर्ज किया गया।

बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों ने दी बाजारों को मजबूती

- क्रूड के 75 डॉलर से नीचे आने के कारण भी तेजी को मिला सपोर्ट
- बेहतर तिमाही नतीजे के बल पर टाटा स्टील करीब सात फीसद उछला

मुंबई, प्रेट्र : बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर के हैवीवेट शेयरों में खरीदारी बढ़ने से शुक्रवार को देश के शेयर बाजारों में उछाल दर्ज किया गया और प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स ने फिर से 39,000 का स्तर हासिल कर लिया। बीएसई का सेंसेक्स 336.47 अंक उछलकर 39,067.33 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 112.85 अंक मजबूत होकर 11,754.65 पर बंद हुआ। पूरे सप्ताह के कारोबार में हालांकि सेंसेक्स में 72 अंकों की गिरावट रही, जबकि निफ्टी में 1.85 अंकों की तेजी दर्ज की गई।

सेंसेक्स में टाटा स्टील में सर्वाधिक 6.67 फीसद उछाल दर्ज किया गया। कंपनी ने जनवरी-मार्च 2019 तिमाही में अपने समेकित शुद्ध लाभ में बढ़ोतरी दर्ज की है। शेयरों में बढ़ोतरी से बीएसई पर टाटा स्टील का बाजार पूंजीकरण (एमकैप) 933.49 करोड़ रुपये बढ़कर 62,451.49 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। कंपनी ने गुरुवार को बाजार बंद होने के बाद तिमाही नतीजे की घोषणा की थी। आइसीआइसीआइ बैंक में तीन फीसद से अधिक तेजी रही। एक्सिस बैंक और टीसीएस दो फीसद से अधिक उछले। भारतीय स्टेट बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज एक फीसद से अधिक मजबूत हुए। 30 शेयरों वाले इंडेक्स में सिर्फ यस बैंक को छोड़कर बैंकिंग और फाइनेंस के बाकी सभी शेयरों में मजबूती दिखी। सेंसेक्स में टाटा मोटर्स में सर्वाधिक 2.84 फीसद की गिरावट रही। मारुति और भारती एयरटेल भी एक फीसद से अधिक फिसले।

कृषि समाधान पर काम करने वाली कंपनी रालिस इंडिया के शेयरों में बीएसई पर 4.04 फीसद गिरावट रही। कंपनी ने गुरुवार को अपने समेकित शुद्ध लाभ में 93 फीसद गिरावट दर्ज की थी। सेक्टरों के लिहाज से बीएसई के धातु सेक्टर में 1.92 फीसद की सर्वाधिक तेजी रही, जबकि वाहन सेक्टर में सर्वाधिक 1.06 फीसद की गिरावट रही। बाजार के अस्थायी आंकड़ों के मुताबिक गुरुवार को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआइ) ने 3,785.73 करोड़ रुपये के शेयरों की शुद्ध खरीदारी की, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआइआइ) ने 4,069.98 करोड़ रुपये के शेयरों की शुद्ध बिक्री की।

एशिया के अन्य प्रमुख बाजारों में शंघाई, टोक्यो और सियोल के बाजारों में गिरावट रही। एचडीएफसी सिक्युरिटीज के रिटेल रिसर्च प्रमुख दीपक जसानी ने कहा कि चीन में राहत पैकेज के जारी नहीं रहने की आशंका के कारण साप्ताहिक आधार पर इसके बाजार में अक्टूबर 2018 के बाद सबसे बड़ी गिरावट आई है। यूरोप में भी प्रमुख बाजारों के शुरुआती कारोबार में गिरावट का रुझान देखा गया।

मौसम विशेष

जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में मौसम शुष्क और आरामदायक बना रहेगा। राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में लू संभव है। पंजाब, हरियाणा तथा दिल्ली में भी मौसम गर्म हवाओं के साथ काफी गर्म बना रहेगा। आसमान मुख्यतः साफ तथा प्रदूषण की मात्रा में वृद्धि होगी।

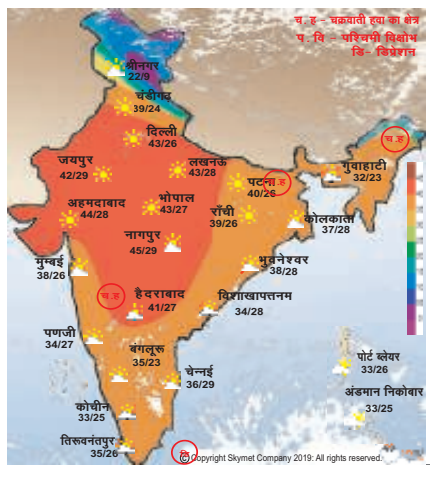

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	37/25/ध	अहमदाबाद	41/22/ध
कोलकाता	37/28/स	बड़ौदा	40/22/आंबा
चेन्नई	35/28/आंबा	नागपुर	45/28/ध
हैदराबाद	41/27/स	इन्दौर	41/24/स
बंगलूरु	36/23/स	रांची	40/25/ध
त्रिवेन्द्रम	35/26/आंबा	पटना	44/30/स
गुवाहाटी	30/23/स	जमशेदपुर	36/26/आंबा
गंगटोक	15/03/आंबा	पुणे	27/20/स